**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)** : (क) और (ख) तेल कम्पनी द्वारा चुने हुये उम्मीदवार को आशय पत्र जारी करने के बाद उम्मीदवार द्वारा अनेक वैधानिक और अन्य औपचारिकतायें पूरी करनी होती हैं और सुविधायें बनानी होती हैं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी चुने हुये उम्मीदवारों के विरुद्ध शिकायतों तथा न्यायालय से स्थगन आदेशों के कारण भी प्रगति रुक जाती है। इसलिये यह कहना संभव नहीं है कि कब तक एल०पी०जी वितरण केन्द्र या खुदरा बिक्री केन्द्र (मोटर स्प्रिट/हाईस्पीड डीजल) की डीलरशिप वास्तव में खुल जायेगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उन मामलों की संख्या जिनमें आशयपत्र जारी कर दिये गये हैं इस प्रकार है :—

| | उत्तर प्रदेश | हरियाणा |
|---|---|---|
| खुदरा बिक्री केंद्रों (मोटर स्प्रिट/डीजल) की डीलरशिपें | 57 | 16 |
| एल०पी०जी० वितरण केन्द्र | 40 | 16 |

उपर्युक्त में से कुछ के चालू वर्ष के दौरान कार्य आरम्भ कर देने की सम्भावना है।

**1982, 1983 और 1984 के पंजीकृत ग्राहकों को एल०पी०जी० के नए कनेक्शनों का दिया जाना**

1341. **श्री सुनील कुमार पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ माह पूर्व दिल्ली में और विशेष रूप से दिल्ली के पूर्वी भाग में, इंडियन आयल कारपोरेशन के एल०पी०जी० वितरकों को कारपोरेशन द्वारा ऐसे आवेदकों को जिन्होंने 1982-83 और 1983-84 में गैस कनेक्शन के लिये पंजीकरण कराया था, एल०पी०जी० के नये कनेक्शन जारी किये जाने के निर्देश दिये गये थे, और क्या यह भी सच है कि आई०ओ०सी० के उच्च अधिकारियों ने ऐसे गैस कनेक्शन जारी करना बन्द कर दिया है जिसके कारण स्थानीय निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार उक्त आवेदकों को चालू वर्ष में एल०पी०जी० के कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है; और

(ग) ऐसे वितरकों के नाम क्या हैं जिन्हें इंडियन आयल कारपोरेशन ने गैस कनेक्शन जारी करने से रोक दिया है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता। तथापि, उत्पाद की उपलब्धता, उपकरण और सुविधायें होने पर चरणबद्ध रूप से उन वितरकों के माध्यम से जिनके पास अधिकतम सीमा से कम कनेक्शन है, नये कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

**Schemes for establishing Growth Centres in backward areas**

1342. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have phased out and replaced with the scheme of establishing 'Growth Centres' located in the backward areas in the countryside in place of 'no industry districts'; if so, the names and location of such growth Centres, State-wise;

(b) what facilities and incentives Central Government would extend for setting up of new industries in such growth Centres; and

(c) what facilities and incentives State Government would extend to new industrial units to be set up in

such growth Centres besides Central Government, Statewise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) The Government have decided to set up 100 growth centres all over the country which will act as magnet to attract industries. The location of such growth centres will be decided in consulation with the State Governments concerned. Industries set up in such growth centres will get facilities and incentives that are normally extended to industries set up in backward areas. It is for the State Governments concerned to decide on the facilities and incentive that will be extended by them in these growth centres.

**एच० बी० जे० पाइपलाइन के माध्यम से मध्य प्रदेश को अधिक गैस का दिया जाना**

1343. **श्री अजीत जोगी:** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 14 मार्च, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1967 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) एच०बी०जे० पाइपलाइन से किये जा रहे अतिरिक्त गैस प्रदाय को देखते हुए, क्या मध्य प्रदेश को और अधिक गैस उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई तकनीकी और आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के निष्कर्ष क्या हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)** : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में किसी नई परियोजना के लिये गैस देने के लिये आगे कोई वचन नहीं दिये हैं ।

**Involvement of foreign company in the HBJ pipeline deal**

1344. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether any foreign agency/ concern was involved in the Hazira-Bijaipur-Jagdishpur (HBJ) gas pipeline deal;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the World Bank have shown their interest for investment in HBJ Pipeline;

(d) if so, whether the proposal for investment of World Bank was ignored and a private foreign company was favoured; and

(e) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) and (b) The execution of the HBJ Pipeline Project involved inviting tenders for the two major components;

(i) Supply of line pipes; and

(ii) composite contract for laying the pipeline and associated facilities.

Global tenders were invited for both the line pipes and composite contract for the pipe laying and associated facilities. Orders were placed with the following parties for purchase of line pipes:

(i) Japanese Consortium

(ii) Interbras Petrobrass Brazil

(iii) Bergrohr, Gombh, West Germany and

(iv) Sider Export, Italy.